

प्रेषक,

डा० हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
ऊधमसिंहनगर/चम्पावत/पौड़ी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 31 जनवरी, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु जिला योजना डी०आई०सी० के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण में प्रथम अनुपूरक मांग में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 405/रा०यो०आ०/जि०यो०/2007-08 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु आयोजनागत पक्ष के डी०आई०सी० के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण जिला योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग में व्यवस्थित धनराशि, जनपद ऊधमसिंहनगर हेतु ₹0 37.55 लाख, जनपद चम्पावत हेतु ₹0 10.00 लाख तथा जनपद पौड़ी हेतु ₹0 3.00 लाख अर्थात् कुल ₹0 50.55 लाख (रुपये पचास लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि के व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 405/रा०यो०आ०/जि०यो०/2007-08 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो, व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय स्टोर चर्ज रूल्स/टेन्डर/कोटेशन/डी०जी०एस०एण्ड डी० के नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक: 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। न्यूनतम तक स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण शासन को उद्योग निदेशालय के माध्यम से प्रत्येक माह प्रेषित किया जायेगा।

5- धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ये जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लान परियोजना के अन्तर्गत हो और जिला योजना में अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परियोजना के अनुरूप ही हो।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-23 लेखाशीर्षक 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परियोजना, 00-आयोजनागत, 102-लघु उद्योग, 05-डी0आई0सी0 के आवासीय/अवासीय भवनों का निर्माण-00-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 16/XXVII(2)/2008 दिनांक 28 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

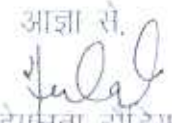
भवदीया

(डा० हेमलता ढोंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 6226(1)/VII-2/353-उद्योग/04, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत/पौड़ी।
8. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-2
12. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(डा० हेमलता ढोंडियाल)
अपर सचिव।